Implementation of Dahej Uran Pipline

*307. SHRI DATTAMEGHE: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the details of progress made in the implementation of the Dahej Uran Pipeline, so far;

(b) how much gas is proposed to be supplied to Maharashtra for feeding industrial, power and other projects since Maharashtra falls on the pipeline project indicating the number and nature of the projects to be fed; and

(c) whether Maharashtra Government has laid its claim or otherwise requested for additional gas supply; if so, the details in this regard and Government's response thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR) (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The progress of Dahej-Uran Pipeline Project (DUPL) of GAIL is as under:—

(i) RoU (Right of User) Acquisition-Completed.

(ii) Road/Rail Crossing permissions-Obtained.

(iii) Environmental clearance-Obtained.

(iv) Line pipe—Notice Inviting Tender has been floated for procurement of line pipe on 29.7.2005.

The project is expected to be completed by February 2007.

(b) GAIL (India) Limited have signed Termsheet/Heads of Agreement for supplying 7.23 million standard cubic metres per day (MMSCMD) of gas to potential industrial consumers in various sectors, *viz.,* Fertilizer, Steel, Ceramics, Petrochemicals, Textiles, etc., in Maharashtra through DUPL Pipeline.

Further, Heads of Agreement for transportation of gas, to begin with 2 MMSCMD and increasing up to 5 MMSCMD, have been signed for supplies to the power sector.

However, the additional source of supply of gas is yet to be firmed up. Arrangements are being made to tie up additional gas/Liquefied Natural Gas (LNG) to provide for the requirement given above.

(c) Government of Maharashtra have requested implementation of Dahej-Uran gas pipeline on a fast track and for immediate additional supplies of natural gas to be consumers in Mumbai and Pune. They have been apprised of the progress with regard to the different parameters of project.

श्री दत्ता मेघे : सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एलएनजी गैस की मांग के बारे में, गेल इंडिया लिमिटेड ने 2001 में सर्वेक्षण किया था, तभी से महाराष्ट्र को एलएनजी की अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने का मुद्दा पेंडिंग है, लेकिन अभी कोई असर नहीं हुआ है । पहले दाभोल में एलएनजी टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें महारष्ट्र को 20 घनमीटर गैस मिलती थी, लेकिन इस समय महाराष्ट्र को इस समय 89 MMSCMD, नेच्युरल गैस मिल रही है, जो इसके आबंटित भाग का केवल 50 परसेंट है । इससे उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दाहेज-उरान गैस पाइपलाइन परियोजना फरवरी 2005 में पूरी होनी थी, अब तक पूरी नहीं हो पाई, इस परियोजना को पूरा होने में विलम्ब क्या था, और इसके कारणों को दूर करने के क्या तात्कालिक उपाय किए गए हैं ?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, mere provision of a pipeline does not provide gas You have to tie up gas first before... *(Interruptions).*

श्री दत्ता मेघे : मेरा क्वेश्चन है कि **...(व्यवधान)**...

श्री दत्ता मेघे : महारष्ट्र में उनका 50 परसेंट है, उसका जवाब देना चहिए । **...(व्यवधान)**... हमको पाइपलाइन मालूम है ।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैने बस यह स्पष्टीकरण दिया है कि पाइपलाइन लगाने से गैस नहीं पहुंचेगी, उस पाइपलाइन के अंदर गैस डालने की जरूरत है ।

जैसाकि मैने आपको अंक "बी " में लिखित बताया है, "Additional source of supply of gas I yet to be firmed up." हम कोशिश कर रहे हैं । एल.एन.जी. का आयात करने के लिए हम दुनिया भर में घूम रहे हैं, क्योंकि इसके आयात की आवश्यकता है । मैं ईरान गया हूं, कतार भी गया हूं, साउदी अरेबिया गया हूं, ओमान भी जाने वाला हूं । जहां तक दाबोल

टर्मिनल का सवाल है, माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रोजेक्ट को पुनर्जिवित करने के लिए प्रयास जारी है। इस सिलसिले में यदि दहेज पर हमें दहेज पावर स्टेशन की मांगों के अतिरिक्त और थोडी-बहुत गैस मिले तो हम उसे इस पाइपलाइन के अंदर डालेंगे । हमने गेल पर बहुत जोर डाला है कि आपको दो चीजें करनी हैं, आप न केवल उपभोक्ताओं की खोज में निकलिए, बल्कि आप गैस की खोज में भी निकलिए ताकि इस पाइपलाइन के अंदर गैस डाली जाए । मान्यवर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली फरवरी, 2007 तक हम इस पूरे प्रोजेक्ट को कर देंगे, लेकिन इसकी बुनियाद यही होगी कि हमें कहीं न कहीं से गैस मिले और इसके लिए प्रयास जारी है ।

श्री दत्ता मेघे : सभापति जी, मेरा प्रश्न यह नहीं है । मैंने यह पूछा है कि जो अलोटमेंट है, एल.एन.जी. फिफ्टी परसेंट दे रहे हैं, इन्होंने उसके बारे में उत्तर नहीं दिया है ।

श्री मणि शंकर अय्यर : उसका भी जवाब दे देंगे ।

श्री दत्ता मेघे : मेरा प्रश्न यह है, मैंने माननीय मंत्री से उत्तर पूछा है , उन्होंने आखिर में जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सरकार को बता दिया है । उन्होंने सरकार को बता दिया है, लेकिन मैं किससे पूछूं सर ? जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब वे मुझे दें सर ...(**व्यवधान**)... उन्होंने ऐसा कहा है कि हमने सरकार को बता दिया है ...(**व्यवधान**)... हाउस को मालूम है ...(**व्यवधान**)... वे क्यों प्रश्न पूछेंगे ? मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है ...(**व्यवधान**)... उत्तर में आता है कि हमने सरकार को बता दिया है ...(**व्यवधान**)... वे क्यों पूछेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : उन्होंने आपको सरकार मान लिया है ।

श्री दत्ता मेघे : सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या यह सच है कि मुम्बई हाई में ओ.एन.जी.सी. के प्लेटफार्म के नष्ट हो जाने के बाद महाराष्ट्र में नेचुरल गैस की सप्लाई का संकट और गहरा गया है ? ऐसी स्थिति में दाहेज उरान गैसे पाइपलाइन पूरी होने तक महाराष्ट्र को नेचुरल गैस की अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने के लिए संबंध में आप क्या कर रहे हैं ? यह बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री सभापति : इनके पास पाइपलाइन है और आपके पास गैस नहीं है ।

श्री मणि शंकर अय्यर : सभापति जी, मैं मानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । मैं पहले ही स्पष्टीकरण दे दूं कि सवाल में माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस विषय को हमारे सामने रखा है और हमारी सरकार का उस सवाल का क्या जवाब रहा है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हमने उन्हें जवाब भेज दिया है । क्योंकि मैं जानता था ...(**व्यवधान**)...

श्री दत्ता मेघे : उत्तर दिया है ...(**व्यवधान**)... हमने यह पूछा है ...(**व्यवधान**)... महारष्ट्र में गैस नहीं है ...(**व्यवधान**)... लोग चिल्ला रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठिए, उन्होंने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार को जवाब दे दिया है, बात खत्म हो गई, इससे गैस थोड़े ही बनती है ...(**व्यवधान**)...

श्री मणि शंकर अय्यर : सभापति जी, मैंने 12 अगस्त, 2005 को मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें मैने वही बताया है, जो अभी-अभी माननीय सदस्य को बताया है कि,, DUPL is scheduled for completion in February, 2007. The Dabhol **LNG** terminal is also likely to be commissioned by next year. A part of the LNG from the Dabhol LNG terminal might be available for distribution to consumers in the Uran region. Thus the position of gas supplies for consumers in the Uran region may ease from 2007 onwards, जहां तक मांग का सवाल है, हमारे आंकड़ों के मुताबिक मांग तकरीबन 160 मिलियन स्टैण्डर्ड क्युबिक मीटर पर डे की है और जो उपलब्धता है, जो गैस उपलब्ध है, वह मात्र 90 मिलियन स्टैण्डर्ड क्युबिक मीटर पर डे है । लाज़िमी है कि महारष्ट्र में भी गैस की कुछ कमी होगी, जैसा कि देश भर में कुछ कमी है । अभी फिलहाल हम 9,10 मिलियन स्टैण्डर्ड क्युबिक मीटर पर डे, महारष्ट्र को मुम्बई हाई से उपलब्ध करा रहे थे । इस हादसे के पश्चात मुझे डर था, मुख्यमंत्री जी को डर था कि कोई भी गैस हम वहां से यहां नहीं पहुंचा पाएंगे ।

लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ONGC को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने पाइपलाइन की लूपिंग करके, एक और प्लेटफार्म NQ के द्वारा गैस उपलब्ध कराई और जहां पहले महारष्ट्र को तकरीबन 9 मिलियन SCMD मिलती थी, अब सितंबर के पहले हफ्ते तक हम 6 मिलियन SCMD यानी 70 प्रतिशत पहुंचा देंगे । मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है कि हम पावर सैक्टर को प्राथमिकता देंगे, लेकिन साथ-साथ फर्टिलाइज़र को भी कुछ देने की जरूरत है। इस पर बातचीत जारी है । पावर और फर्टिलाइज़र, दोनों को हम महाराष्ट्र में जिवित रखेंगे ।

श्री लेखराज वचानी : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दहेज, गुजरात में है और दहेज दे पास एक गैस बेस्ड पावर स्टेशन बन रहा है । उस वक्त केन्द्र सरकार ने जितनी गैस चाहिए, उतनी मिलेगी, ऐसा आश्वासन दिया था । क्या उस आश्वासन के मुताबिक गुजरात के बेस्ड पावर हाउस को गैस दी जाएगी? इसके लिए बार-बार गुजरात सरकार और वहां के ऍम.पीज. की ओर से माननीय मंत्री जी के सामने रिप्रैजेंटेशन हो रहा है । हमें समय पर पूरी गैस दी जाएगी, क्या ऐसा आश्वासन मंत्री जी देंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर : दहेज में जो गैस मिलती है, उसके लिए GAIL तय कर रही है कि किन-किन के साथ परचेज और सप्लाई ऐग्रीमेंट्स करने हैं । मेरी सूचना के अनुसार बहुत से उपभोक्ताओं के साथ कुछ न कुछ समझौता हो चुका है । इसमें बताया गया है कि, "Heads of agreement for transportation of gas, to begin with 2 million standard

cubic metres per day (MMSCMD) and increasing up to 5 MMSCMD, have been signed for supplies to the power sector". वह जो पावर प्लांट, दहेज के बगल में लग रहा है, यदि अब तक उन्होंने GAIL के साथ समझौता नहीं किया है, तो मैं उन्हें यह मशविरा देता हूं कि उनके साथ बातचीत शुरू कीजिए और समझौता कीजिए। जो गैस वहां आती है, उसके मुताबिक आपको भी उपलब्ध होगी।

श्री ललितभाई मेहता : मंत्री जी, इसमें सवाल यह है कि आप जो देने की बात कर रहे हैं, वह जो मार्किट रेट से देने की बात कर रहे हैं। एक रेट 3,200 रूपए है, दूसरा 6,000 रूपए है **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : आप अपनी गवर्नमेंट से बात करा दीजिए।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, while asking his question, Mr. Meghe, had said specifically that this pipeline was to be commissioned by 2005; and now, as it appears, since, for pipe procurement, a notice inviting tender has been given in 2005 itself, it has been delayed. This subject has been widely publicised here, and certain committees are going into this. My only question to the hon. Minister is this. जैसा इन्होंने कहा कि वे इतने बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, there has been a delay for two years because of this tendering of the pipeline. Without going into the details of technical specifications and all that, someone has to be made administratively responsible. I want to know whether the Ministry will see to it that someone is made accountable for this delay—whosoever is responsible.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, it is only on account of the intervention of this Ministry that the kind of criticism, to which the hon. Member is referring, especially in the media, has been fully and satisfactorily addressed. Had it been addressed in the same manner by the GAIL Board, without a presidential directive from the Ministry, perhaps, the work could have begun on this much earlier. But, notwithstanding the media reports and all the details that were being put out in the media about the two different types of technology that can be used for making this kind of piping, had the GAIL Board taken a slightly different attitude, maybe, we would have got going. But I did not think—and I take this responsibility entirely on myself—that we should allow a process of tendering that could raise doubts in the minds of people to go through in preference to having a completely transparent system of tendering put in place.

In any case, it did not make much difference whether it would be completed by 2005 or 2007, because the key question was the sourcing of gas. We still not sourced the gas. I do hope that we will be able to do so by the time we have commissioned the pipeline in February, 2007.

Revision of listing norms by SEBI

*308. SHRIMOTILALVORA:†
SRIMATI PREMA CARIAPPA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether in order to give relief to the small size companies, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has reviewed and revised the listing and delisting norms:

(b) if so, the details of major changes and modifications being so made including the reasons for such changes; and

(c) the steps since taken in this direction?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) (a) to (c): A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The SEBI (Delisting of Securities) Guidelines, came into effect on February 17, 2003. These guidelines govern "voluntary and compulsory delisting of securities. A view has been expressed in some quarters that the present procedure for delisting is onerous for small companies. Action has been initiated to address alternatives and to identify a solution that is also consistent with the interests of small investors.

SEBI has not undertaken any review of listing norms for small sized issues.

SHRI MOTILAL VORA: Sir, I had asked whether in order to give relief to the small size companies, the securities and Exchange Board of India has reviewed the listing and delisting norms, the hon. Minister has replied that the SEBI (Delisting of Securities) Guidelines came into effect in February, 2003. Sir, these guidelines, as the Minister himself admitted,

†The question was actually asked on the floor of the house by Shri Motilal Vora